अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

चुनावी घोषणा पत्र 2021

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
चुनावी घोषणा पत्र 2021

अपील

मैं पश्चिम बंगाल के प्रत्येक व्यक्ति का पिछले 10 वर्षों के दौरान तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने के लिए अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूं। जब हमने 2011 में अपनी सरकार बनाई थी तो हम बंगाल को प्रगति, शांति और समृद्धि के नये शिखर पर ले जाने के विलक्षण उद्देश्य से प्रेरित थे और हम अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में बेमिसाल रहे हैं। इस यात्रा में हमारे साथ समाज के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने हमें बंगाल में समग्र विकास के लिए मजबूत बुनियाद रखने में मदद की है। उस दिन के बाद से मिशन मोड में हमारे द्वारा की गयी कई पहलों ने लोगों के जीवन को बदल दिया है, जो हमें हमें राज्य की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करने को प्रेरित करती है। विकास की आधारशिला जो हमने पिछले एक दशक में बंगाल में रखी है, उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और मैं आने वाले वर्षों में भी प्रगति और विकास की इस गति को बनाए रखने की प्रतिज्ञा करती हूं।

अब पिछले 10 वर्षों में हमने जो असाधारण कार्य किया है, उस पर चर्चा करने का समय आ गया है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव से गुजरने के बावजूद, हमारे समर्पण और कड़ी मेहनत ने बंगाल को कई क्षेत्रों में शीर्ष-रैंकिंग राज्य के रूप में स्थापित किया है। पिछले दशक में, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, और हमारे राज्य के बजट में तीन गुना वृद्धि हुई है, जबकि लोगों की औसत आय दोगुनी से अधिक हो गयी है। हर घर में साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए कन्याश्री योजना के माध्यम से लाखों छात्राओं को वित्तीय सहायता दी गयी है। बंगाल का प्रत्येक नागरिक अब स्वास्थ्य साथी योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। खाद्य साथी योजना के माध्यम से हमने रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान कर खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी है। बांग्ला आवास योजना के तहत हमने सुनिश्चित किया है कि ग्रामीण परिवार अब पक्के घरों में रह सकते हैं। आज बंगाल के हर घर में बिजली का कनेक्शन है। राज्यभर में बेहतर आवागमन के लिए कई लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत की गयी है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए बजट में लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान, जो हमारे समाज की रीढ़ हैं, की आजीविका बेहतर हुई है। हमने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा को बढ़ाया है। समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए बजट भी दोगुना हो गया है। रोजगार की दिशा में बंगाल ने 100-दिवसीय कार्य योजना में शीर्ष स्थान हासिल

किया है। और मैं वादा करती हूं कि बंगाल अगले पांच वर्षों में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करते हुए अर्थव्यवस्था, उद्योग, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन और अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, एससी/एसटी समुदायों के कल्याण की दिशा में नेतृत्व प्रदान करता रहेगा।

हमारे बंगाल में कई धर्मों, जातियों, समुदायों, पंथों और मान्यताओं का उल्लेखनीय समन्वय है। हम एकता और विविधता में विश्वास रखते हैं और यह हमारी संस्कृति और परम्परा का अभिन्न अंग रहा है। यह आदर्श हमारी विरासत है, जो हमें रवींद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कवि काजी नजरूल इस्लाम, ठाकुर पंचन बर्मा, बाबासाहेब अंबेडकर, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर,बिरसा मुडा, रघुनाथ मुर्मू, महात्मा गांधी, सिद्धू, कान्हू, गुरु नानक, मातंगिनी हाजरा, मास्टर सूर्य सेन, खुदीराम बोस और कई अन्य महान विभूतियों से हमें विरासत में मिली है। इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और भारत की इस विचारधारा के प्रति बंगाल की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। और बंगाल की बेटी के रूप में मैं हमेशा अपनी मातृभूमि की ऋणी रहूंगी और मैंने स्वयं को उसकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया है।

भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। हालांकि, पिछले सात वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की केंद्र सरकार इसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ चल रही है। इसने तानाशाही हमलों के साथ लोगों के जीवन को नष्ट और तबाह कर दिया है। इसने हमारे देश के कई सम्मानित संस्थानों को कमजोर किया है। हर दिन हम देशभर में महिला सुरक्षा को लेकर कुछ न कुछ अप्रिय समाचार सुनते हैं, साथ ही हमारे दलित भाइयों और बहनों के साथ होने वाले जुल्म, हमारे किसानों की आवाजों को कुचलने और इस तरह के तमाम दमन की खबरें। सार्वजनिक सेवा के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान मेरा मुख्य उद्देश्य हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना रहा है। ऐसे गंभीर समय में, जो हमारे देश में है, मैं पूरी तरह से उनलोगों के लिए आवाज उठाने का संकल्प लेती हूं, जो अन्य राज्यों में अत्याचार का सामना कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर उत्पीड़न की ऐसी सभी ताकतों को अपनी पवित्र भूमि में प्रवेश करने से रोकने का संकल्प लेती हूं।

वर्ष 2020 वैश्विक समुदाय के साथ-साथ बंगाल के लिए एक कठिन वर्ष था। जब हम कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार की दिशाहीन नीतियों से जूझ रहे थे तभी हमने सुपर चक्रवात अम्फान के कारण होने वाले कहर का भी सामना किया। ऐसे कठिन समय में भी संघवाद की भावना के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार ने हमें नगण्य समर्थन प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल के लोगों को हजारों करोड़ रुपये की धनराशि से वंचित किया, जिसके हम वैध रूप से हकदार थे। हालांकि, हमने कभी हार नहीं मानी और हमारी सरकार ने लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए कई विकासात्मक पहल शुरू की। मैं संकट के ऐसे गंभीर समय में भी बंगाल के लोगों की अपनी बेटी के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए हृदय से उनकी ऋणी हूं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बंगाल का विकास आगे बढ़ता रहे और तीसरी बार हम लोगों की सेवा कर सकें, मैं बेहतर और समृद्ध बंगाल के निर्माण के लिए विनम्रतापूर्वक 10 वादे कर रही हूं। राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ व्यापक परामर्श के बाद इन्हें तैयार किया गया है। बंगाल को देश के अग्रणी राज्यों में से एक में बदलने के लिए मेरे 10 वादे हमारे शासन का आधार स्तंभ बनेंगे और आगे के पांच वर्षों के लिए यह मेरा रोड मैप होगा।

बंगाल देश की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और हम 35 लाख लोगों के चरम गरीबी रेखा से

बाहर आने को सुनिश्चित करेंगे। युवाओं के लिए हम हर साल 5 लाख नये रोजगार सृजित करेंगे और निश्चित रूप से बेरोजगारी दर को कम करेंगे। पहली बार एक नयी योजना शुरू की जा रही है, जिसमें 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया हमारी सरकार द्वारा प्रदान की गयी 500 रुपये की मासिक आय सहायता से लाभान्वित होंगी साथ ही एससी तथा एसटी समुदाय के परिवारों को 1000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। सभी सुयोग्य छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए एक नयी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड में आसान पुनर्भुगतान के प्रावधान के साथ केवल 4% की ब्याज दर के साथ इसमें 10 लाख रुपये तक के ऋण लेने की सुविधा होगी। खाद्य साथी योजना के तहत नयी सुविधाओं के तौर पर डेढ़ करोड़ परिवारों को मासिक राशन की डिलीवरी उनके दरवाजे पर होगी। किसान हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं, उनका कल्याण और जीवन की गुणवत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए, हम कृषक बंधु योजना के माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपये की सहायता प्रदान करने जा रहे हैं। छोटे और मध्यम उद्यमी बंगाल के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सालाना 10 लाख नये एमएसएमई बनेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल में प्रत्येक परिवार को जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सभ्य मानक की गारंटी दी जाए। इसके लिए, हम स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए राज्य के व्यय में वृद्धि करने जा रहे हैं, कम लागत वाले 25 लाख आवास बनाए जाएंगे और प्रत्येक घर में पीने के पानी और बेहतर जल निकासी की व्यवस्था होगी।

मैं मंडल आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समुदायों जैसे माहिष्य, तिली, तामुल तथा साहा को ओबीसी की स्थिति में लाने की जांच और इसकी सिफारिश करने के लिए एक विशेष कार्यबल नियुक्त करूंगी। इसके साथ ही मालदा जिले के कुछ हिस्सों में अनुसूचित जनजाति के रूप में रहने वाले किसान जाति की मांगों को पूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं महतो समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ आक्रामक रवैया अपनाऊंगी। तराई-डुआर्स के लोगों के समग्र विकास और उत्थान के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसका क्षेत्र के सभी समुदायों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। मैं चुने हुए प्रतिनिधियों सहित पहाड़ों में रहने वालों स्थानीय लोगों और प्रमुख जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करूंगी ताकि क्षेत्र में दीर्घकालीन शांति और विकास के लिए प्रयास किया जा सके साथ ही एक स्थायी राजनीतिक समाधान तक हम पहुंच सके।

इन 10 बुनियादों की नींव हमारे पहले दो कार्यकालों में रखी गयी थी, जिससे हमें आने वाले वर्षों में बंगाल को महान ऊंचाइयों पर ले जाने की गति मिली। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वादे करते हैं। हम परिणाम देते हैं।

मैं, ममता बैनर्जी, अपने मां- माटी- मानुष से जोड़ा-फूल पर बटन दबाकर अपना कीमती वोट डालने की अपील करती हूं। तृणमूल को वोट दें। 'बंगाल की अपनी बेटी' को वोट दें। हमें बाहरी लोगों का विरोध करना चाहिए और हमारे राज्य बंगाल में शांति, सद्भाव और बंगाल की नैतिकता की रक्षा के लिए यह सब करना चाहिए। अगले 5 वर्षों में मैं असंभव को संभव में बदलने की प्रतिज्ञा लेती हूं। अपने सभी आशीर्वाद, समर्थन और प्यार के साथ आइए, हम साथ में तृणमूल कांग्रेस सरकार का लगातार तीसरी बार गठन करें।

जय हिंद, जय बांग्ला। जय मां-माटी- मानुष।

ममता बैनर्जी

সৎ
মমতাময়ী
আদর্শবাদী
গণতান্ত্রিক
ন্যায়পরায়ণ
দৃঢ়
সুদক্ষ
আপনজন
অগ্নিকন্যা
জননেত্রী
নীতিপরায়ণ
আপোষহীন

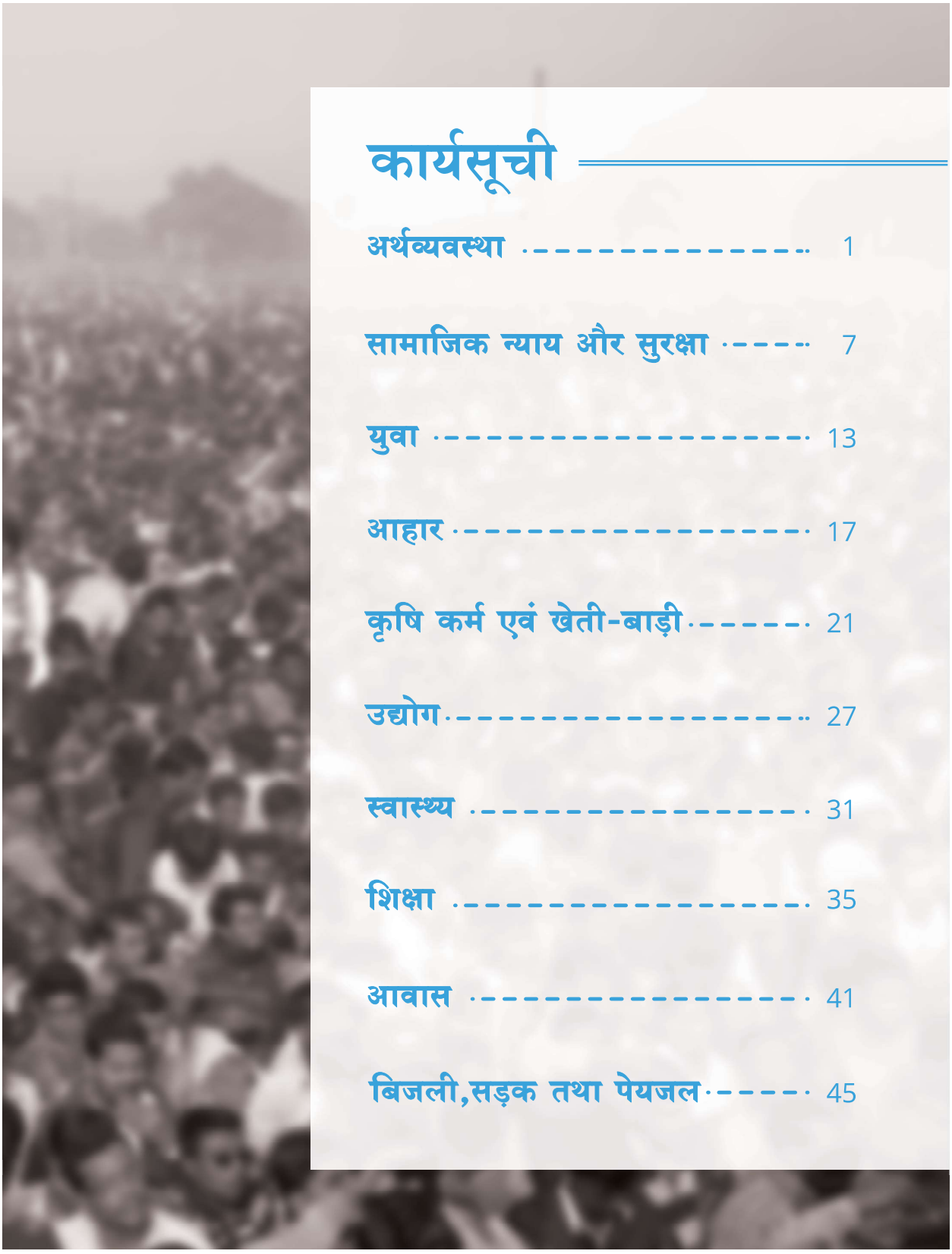

कार्यसूची

अर्थव्यवस्था 1

सामाजिक न्याय और सुरक्षा 7

युवा 13

आहार 17

कृषि कर्म एवं खेती-बाड़ी 21

उद्योग 27

स्वास्थ्य 31

शिक्षा 35

आवास 41

बिजली,सड़क तथा पेयजल 45

दीदी के १० अंगीकार

असंख्य सुअवसर, समृद्ध बांग्ला

- १२.५ लाख करोड़ रुपये की जीडीपी के साथ प्रति व्यक्ति २.५ लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के साथ पांचवीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था
- चरम गरीबी सीमा रेखा से नीचे के ३५ लाख लोगों का उद्धार। सन् २०११ में गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहने वाली २० फीसदी आबादी को कम कर पांच फीसदी तक लाना
- प्रति वर्ष पांच लाख रोजगार के अवसरों का सृजन कर बेरोजगारी दर को आधा करना

प्रत्येक घर, न्यूनतम मासिक आय

- पहली बार बंगाल में हरेक परिवार के लिए न्यूनतम मासिक आय को सुनिश्चित करने के लिए नयी योजना, जिसके तहत १.६ करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को सामान्य श्रेणी के लिए प्रति माह ५०० रुपये का आर्थिक सहयोग (हर घर के लिए वार्षिक ६,००० रुपये) तथा एससी/एसटी परिवारों के लिए प्रति माह १००० (सालाना १२०००) रुपये

आर्थिक सुअवसर, सबल युवा

- बंगाल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी सुयोग्य विद्यार्थियों के लिए नयी योजना- चार फीसदी ब्याज दर के साथ विद्यार्थियों के लिए १० लाख रुपये तक की लिमिट वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

बंगाल में सभी के लिए निश्चित आहार

- खाद्यसाथी योजना में नयी व्यवस्था- अब राशन की दुकानों में जाने की आवश्यकता नहीं।१.५ करोड़ परिवारों के दरवाजों पर मासिक आधार पर राशन का आवंटन।
- सालाना ५० शहरों में २५०० मां कैंटीनों के माध्यम से पांच रुपये में ७५ करोड़ सब्सिडीयुक्त भोजन

उत्पादन वृद्धि, सुखी किसान

- कृषक बंधु योजना के माध्यम से सालाना ६८ लाख छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ १०,००० रुपये की सहायता
- कुल सिंचित क्षेत्र तथा सिंचाई व्यवस्था के तहत ३ लाख हेक्टेयर और बढ़ाकर तथा ४.५ लाख हेक्टेयर अंचल को दो फसली बनाकर राज्य को देश में नंबर १ के स्थान पर ले जाना
- खाद्यान्न तथा चार नकदी फसल- चाय, जूट, आलू तथा तम्बाकू के उत्पादन में देश के शीर्ष पांच राज्यों में स्थान हासिल करना

उद्यमशील बंगाल

- सालाना १० लाख नये एमएसएमई। कुल कार्यकारी एमएसएमई इकाइयों की संख्या १.५ करोड़ से अधिक
- वर्तमान १०,००० औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त आगामी पांच वर्षों में २,००० बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित होंगी
- अगले पांच वर्षों में ५ लाख करोड़ रुपये का नया निवेश

बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वस्थ बंगाल

- स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोगुना आवंटन, राज्य की जीडीपी के ०.८३ फीसदी से बढ़ाकर १.५ फीसदी
- सभी २३ जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज सह सुपर स्पेशियल्टी अस्पताल
- डॉक्टरों, नर्सों तथा पैरा मेडिकों की संख्या को बढ़ाकर दुगना करना

अग्रणी रहने के लिए शिक्षित बंगाल

- शिक्षा के मद में व्यय को राज्य की जीडीपी के २.७ फीसदी से बढ़ाकर ४ फीसदी करना
- हरेक ब्लॉक में कम से कम एक मॉडल आवासीय स्कूल
- टीचर्स ट्रेनिंग स्कूलों में सीटों की संख्या को दोगुना करना

सबके सिर पर मिले छांव

- बस्ती अंचलों में बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत पांच लाख और कम बजट वाले घरों का निर्माण कर बस्तीवासियों की संख्या ७ फीसदी से कम कर ३.६ फीसदी तक लाना
- ग्रामीण अंचलों में बांग्ला आवास योजना के तहत और २५ लाख कम बजट वाले घरों का निर्माण कर कच्चे मकानों का अनुपात घटाकर एक फीसदी से कम करना

हरेक घर को बिजली, सड़क और पेयजल

- और ४७ लाख परिवारों तक पाइपलाइन द्वारा पेयजल पहुंचा कर इसे २६ फीसदी से बढ़ाकर शत प्रतिशत घरों तक पहुंचाना
- सभी घरों में सातों दिन और चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति
- ग्रामीण अंचलों में हरेक घरों तक मजबूत सड़क, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था और नल के द्वारा जल

ITC ROYAL BENGAL

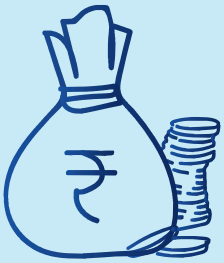

अर्थव्यवस्था

असंख्य सुअवसर, समृद्ध बांग्ला

मुख्य लक्ष्य

- 12.5 लाख करोड़ रुपये की जीडीपी तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक 2.5 लाख से अधिक आय के साथ पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- गरीबी सीमा रेखा से 35 लाख लोगों का उद्धार कर सन् 2011 की 20 फीसदी गरीब आबादी को कम कर पांच फीसदी पर लाना
- बेरोजगारी दर को आधा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 लाख से अधिक नये रोजगार का सृजन करना

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

» **राज्य का सकल देशी उत्पाद (जीएसडीपी) विकास :** पिछले दस वर्षों में बंगाल की जीडीपी (स्थिर कीमतों पर एनएसवीए) 4.51 लाख करोड़ से बढ़कर 6.9 लाख करोड़ (53 फीसदी) बढ़ी है

» **प्रति व्यक्ति आयः** प्रति व्यक्ति औसत आय 2010 के 51,543 रुपये से 2019 में दोगुनी होकर 1,09,491 रुपये हो गयी है

» **राज्य का राजकोषीय घाटा** पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है। राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के तौर पर 2010-11 के 4.24 फीसदी से लगातार घटते हुए 2019-20 में 2.94 फीसदी हो गया है।

» **राज्य का अपना कर राजस्व** पिछले नौ वर्षों में बढ़ा है। यह नौ वर्षों के दौरान लगभग तीन गुना 21,128 करोड़ रुपये से बढ़कर 60,669 करोड़ रुपये हो गया है

» पूंजीगत व्यय में लगभग सात गुना वृद्धि कर 2010- 2011 के 2633.48 करोड़ की तुलना में 2019-2020 में बढ़कर 17,236.83 करोड़ रुपये हो गया है

» **क्षेत्रवार विकासः** कृषि तथा अनुषंगी सेवा के क्षेत्र में 30 फीसदी वृद्धि, उद्योगों की 60 फीसदी तथा सेवा के क्षेत्र में 62 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2010-11 के 84,804 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय से बढ़कर पश्चिम बंगाल के 2021-22 के बजट में अनुमानित व्यय 3.5 गुना अधिक बढ़कर 2.99 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

» **विदेशी पर्यटकों के आगमन** के मामले में पश्चिम बंगाल पांचवें स्थान पर है और वर्ष 2019-20 में केरल और गोवा जैसे राज्यों से आगे था

» **अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात** में 95% वृद्धि और 2011 के बाद से घरेलू यात्री यातायात में 132% की वृद्धि हुई है

» **दुआरे सरकारः** इस पहल के तहत 32,830 शिविर पूरे राज्यभर में लगाए गए तथा 2.75 करोड़ लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं तथा उनकी समस्याओं के तत्काल तथा सहज समाधान के निमित्त कार्य संपन्न हुआ

» **पाड़ाए समाधानः** यह पहल मुख्य रूप से परियोजनाओं को सुदृढ़ या उनके सुदृढीकरण की आवश्यकता पर बल देती है जो या तो रुकी हैं या उन अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने और निवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नयी परियोजनाएं शुरू करने के उद्देश्य पर केंद्रित है।लोगों से मिले भारी उत्साहजनक प्रतिक्रिया के साथ हम 10,000 से अधिक सामुदायिक स्तर के मुद्दों का समाधान करने में सफल रहे

आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्य वादे

1. 12.5 लाख करोड़ रुपये की जीडीपी तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक 2.5 लाख से अधिक आय के साथ पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

पश्चिम बंगाल देश में 7.93 लाख करोड़ रुपये (2019-20) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीडीएसपी (स्थिर कीमतों पर) के साथ छठवीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला राज्य है। विगत दस वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की जीएसडीपी ने 53 फीसदी का विकास देखा है। राज्य की प्रति व्यक्ति सालाना आय वर्तमान (2019-20) में 1.15 लाख रुपये है। साल दर साल राज्य का जीएसडीपी विकास दर सन् 2015 से सन् 2020 तक 6.67 फीसदी रहा है। विकास दर को तेज करते हुए पश्चिम बंगाल 9 फीसदी के वर्द्धित विकास दर के साथ आगे बढ़ेगा तथा राज्य को देशभर की पांचवीं शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल करेगा। इसके साथ ही अतिरिक्त लाभ के तौर पर प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगना कर 2.5 लाख रुपये करेगा।

2. गरीबी सीमा रेखा से 35 लाख लोगों का उद्धार कर सन् 2011 की 20 फीसदी आबादी को कम कर पांच फीसदी पर लाना

राज्य में 1.85 करोड़ लोग (2012) गरीबी सीमा रेखा के नीचे निवास करते थे। सन् 2005- 2012 के बीच साल दर साल गरीबी सीमा रखने के घटने का अनुपात 7 फीसदी था, जो आबादी के विकास के साथ समायोजित था। अगले पांच वर्षों में (2021-26) समेकित विकास तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा के कारण पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त 35 लाख लोगों का चरम गरीबी रेखा से उद्धार होगा।

3. बेरोजगारी दर को आधा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 लाख से अधिक नये रोजगार का सृजन करना

राज्य में करीब 21 लाख लोग बेरोजगार हैं तथा जीडीपी दर में विकास और उद्योग क्षेत्र की बढ़ोतरी के कारण राज्य में हर साल अतिरिक्त पांच लाख रोजगार के अवसर निर्मित होंगे जिससे बेरोजगारी दर घटकर आधी रह जाएगी।

4. पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल

पर्यटन के क्षेत्र में राज्य निरंतर बेहतर कर रहा है। यह 2020 में पांचवें स्थान पर है। इस क्षेत्र में लगातार निवेश के साथ पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू यात्रियों के पर्यटन और आवागमन के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में शामिल होगा।

5. साल में दो बार दुआरे सरकार तथा पाड़ाए समाधान

दुआरे सरकार और पाड़ाए समाधान की अभूतपूर्व सफलता के कारण ये पहल हर साल अगस्त-सितंबर और दिसंबर-जनवरी के दौरान दो बार आयोजित की जाएंगी। हम आश्वस्त करते हैं कि सभी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लाभ हितधारकों को उनके दरवाजे पर ही मिले।

6. सभी प्रमुख पहलों के समुचित क्रियान्वयन के लिए उच्च कार्यकारी इकाई की स्थापना

पश्चिम बंगाल की उच्च कार्यकारी इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन अंतिम परिणाम तक हो तथा उनकी सेवा के स्तर में सुधार तथा उसकी सतत निगरानी करेगी। यह इकाई मुख्यमंत्री के कार्यालय के साथ मिलकर तथा विशेष तौर पर नियुक्त प्रमुख सलाहकार के नेतृत्व के अधीन कार्य करेगी। यह इकाई मुख्यमंत्री के कार्यालय तथा लोगों के बीच दो तरफा समन्वय स्थापित कर लोगों की आकांक्षाओं तथा उम्मीदों का विश्लेषण, फीड बैक तथा सरकारी योजनाओं में व्याप्त कमी पर निगरानी के साथ लगातार राज्य स्तर पर लोगों को योजनाओं के बारे में अवगत करेगी।

7. विधानसभा परिषद का पुनरुद्धार

हम राज्य विधायिका में दूसरे कक्ष के तौर पर विधान परिषद को दोबारा शुरू करेंगे, जिनमें गण्यमान्य को शामिल किया जाएगा, जो सरकार के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। विधान परिषद का गठन भारत के संविधान की धारा 169(1) के तहत राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर किया जाएगा, इसके बाद यह संवैधानिक तौर पर संसद के लिए बाध्यकारी होगा कि वह इस संदर्भ में एक विधि प्रस्ताव पारित कर इसकी औपचारिकता को पूरा करे।

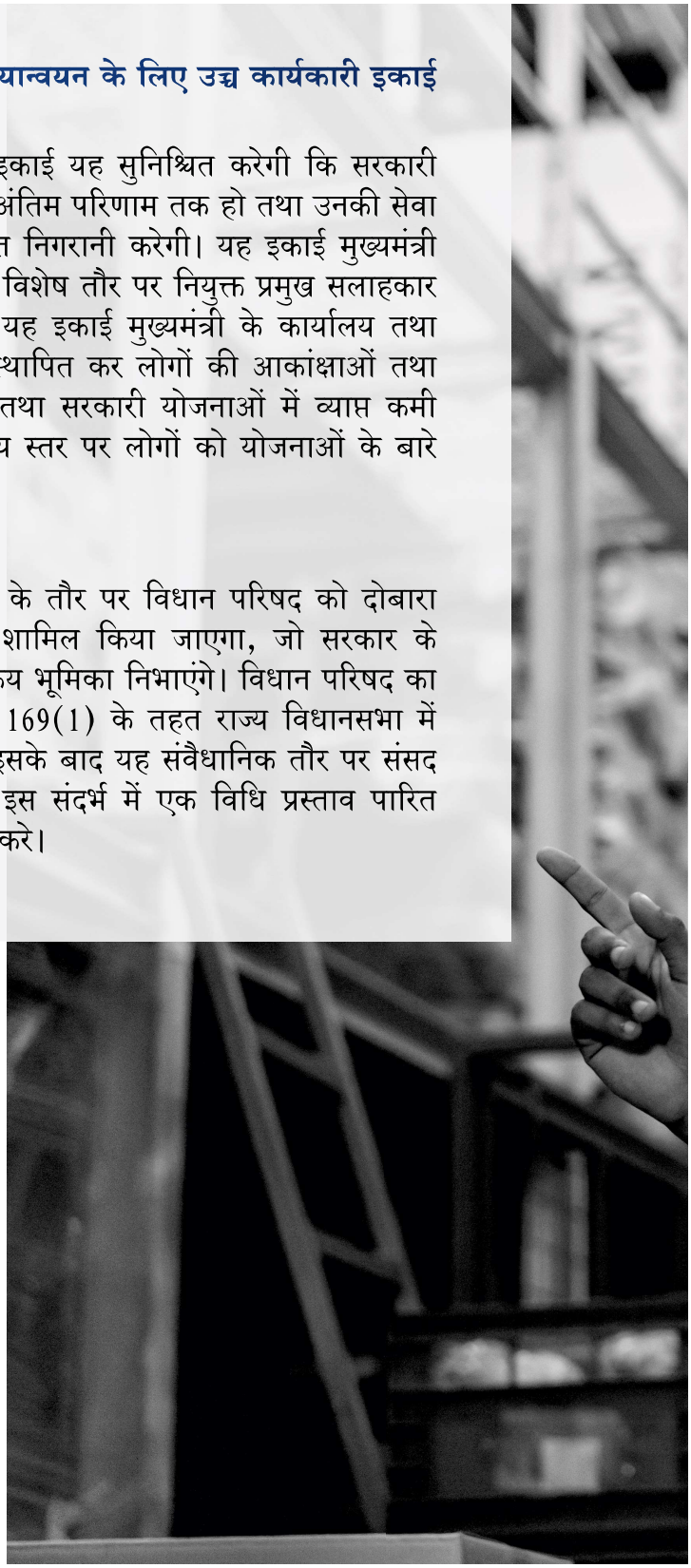

सामाजिक न्याय और सुरक्षा

प्रति बासाय, न्यूनतम मासिक आय

मुख्य लक्ष्य

- पहली बार बंगाल में न्यूनतम मासिक आय को सुनिश्चित करने के लिए नयी योजना, जिसके तहत 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को सामान्य श्रेणी के लिए प्रति माह 500 रुपये का आर्थिक सहयोग (हर घर के लिए वार्षिक 6,000 रुपये) तथा एससी/एसटी परिवारों के लिए प्रति माह 1000 (सालाना 12000) रुपये

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

जंगलमहल क्षेत्र

» **वेस्ट बंगाल केंदू लीव्स कलेक्टर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीमः** पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम के लगभग 35,000 एसटी समाज के व्यक्ति इस योजना के तहत आकस्मिक आपदा, चिकित्सा और अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता के साथ लाभान्वित हुए हैं।

» 2020 में **जंगलमहल बटालियन** का गठन किया गया था जिसका मुख्यालय झारग्राम जिले में है

» 5 जेएपी जिलों के 34 ब्लॉकों में **जंगलमहल एक्शन पैकेज** को लागू किया गया है पहाड़ी क्षेत्र और चायबागान

पहाड़ी क्षेत्र और चायबागान

» वर्ष 2021-22 के **बजट** में इन क्षेत्रों के विकास के लिए 11,523 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं

» **गोरखा बटालियन** का गठन 2020 में दार्जिलिंग जिले में इसके मुख्यालय के साथ किया गया

» प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम मुफ्त अनाज चाय बागान श्रमिकों को प्रदान किया गया है

श्रमिक/मजदूर, संविदाकर्मी और स्वयं सहायता समूह

» **'100-दिवसीय कार्य योजना'** में बंगाल अव्वल राज्य है। विगत 10 वर्षों में, लगभग 60,000 करोड़ की लागत से 260 करोड़ कार्यदिवस उत्पन्न किये गए हैं

» **जागो योजना** द्वारा 9.5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित किया गया, जिसके तहत उन्हें 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की गयी

» **समर्थन योजना** के तहत उन प्रवासी मजदूरों को 50,000 रुपये एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया जो नोटबंदी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य में लौटने के लिए मजबूर हुए थे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण

» **नारायणी बटालियन** का गठन कूचबिहार जिले में उसके मुख्यालय के साथ किया गया

» **जय जोहार** और **तपशीली बंधु** योजना के तहत 60 साल से ऊपर के गरीब एसटी व्यक्तियों को प्रति माह 1,000 रुपये का पेंशन प्रदान किया जाता है

» **जाति प्रमाण पत्र जारी करना :** चालू वित्तीय वर्ष में 19,24,523 जाति प्रमाण पत्र जारी किये गए हैं। प्रमाण पत्रों को तैयार करने और उन्हें जारी करने का समय 8 सप्ताह से घटाकर 4 सप्ताह कर दिया गया है

» **विकास और सांस्कृतिक बोर्ड:** विकास और सांस्कृतिक बोर्ड: तमांग, शेरपा, भूटिया, लिम्बु, आदिवासी और मेयेल लयांग लेप्चा समुदायों के लिए छह सांस्कृतिक और विकास बोर्ड स्थापित किये गए हैं, इसके अतिरिक्त विशिष्ट समुदायों के केंद्रित विकास के लिए, बाउरी, नामशूद्र, मतुआ, राजबंशी, कुर्मी, कामी और बागड़ी समुदायों के लिए विकास बोर्ड स्थापित किये गए हैं

» **वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पट्टों का वितरण :** दिसंबर 2020 तक 48,964 आदिवासियों और 190 अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके द्वारा अधिगृहीत वन भूमि पर उन्हें व्यक्तिगत पट्टे दिये गए हैं

सुंदरवन और तटीय क्षेत्र

» अम्फान चक्रवात के दौरान क्षतिग्रस्त संरचनाओं की पुनर्स्थापना और उनके नवीकरण कार्यों के लिए सरकार ने 263 योजनाओं को मंजूरी दी है

» वर्तमान में, राज्य में कुल 446 बाढ़ आश्रय और 268 राहत गोदाम हैं। इसके अलावा, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के तटीय जिलों में 221 बहुउद्देशीय चक्रवात आश्र. स्थलों (एमपीसीएस) का निर्माण पूरा हो चुका है

शरणार्थी पुनर्वास

» राज्य में 244 शरणार्थी कालोनियों को नियमित किया गया है। इन कॉलोनियों के निवासियों को पूर्ण स्वामित्व वाले पट्टे प्रदान किये गए है जिससे लगभग 45,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं

» 3.5 लाख परिवारों को गृह पट्टा, कृषि पट्टा और वनज पट्टा दिये गए हैं

संस्कृति

» **पुजारियों को वित्तीय सहायता :** राज्य सरकार ने ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी जैसे समुदायों के निचले आय वर्ग के पुरोहितों और पुजारियों के लिए 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मासिक योजना शुरू की है, जिसमें **जय बांग्ला** योजना के तहत आदिवासी भी शामिल हैं

» 2020-21 के दौरान **पश्चिम बंगाल दलित साहित्य अकादमी** का गठन किया गया और **पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी** का पुनर्गठन किया गया है

» **हरिचंद गुरुचंद स्टेडियम** का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसका उद्घाटन किया गया है

» **प्रमुख विभूतियों के लिए राज्य में छुट्टियां :** देशनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, ठाकुर पंचानन बर्मा की जयंती के लिए राज्य अवकाश घोषित किये गए हैं।

आगामी पांच वर्षों के लिए प्रमुख वादे

1. पहली बार हरेक परिवार के लिए न्यूनतम मासिक आय को सुनिश्चित करने के लिए नयी योजना, जिसके तहत बंगाल में 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को सामान्य श्रेणी के लिए प्रति माह 500 रुपये का आर्थिक सहयोग (हर घर के लिए वार्षिक 6,000 रुपये) तथा एससी/एसटी परिवारों के लिए प्रति माह 1000(सालाना 12000) रुपये

राज्य का मासिक औसत उपभोग व्यय 5,249 रुपये है। 500 रुपये की मासिक आय (सालाना 6000 रुपये) की सामान्य श्रेणी की महिलाओं को तथा एससी/एसटी समुदाय के लोगों को प्रति माह 1000 रुपये (सालाना 12000 रुपये) सहायता प्रदान करने से यह उनके मासिक खर्च का क्रमशः 10% और 20% होगा। यह राशि सीधे पश्चिम बंगाल के 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस सार्वभौमिक आय के तहत एससी/एसटी समुदाय के सभी परिवार शामिल रहेंगे। सामान्य श्रेणी के लिए यह आर्थिक सहायता सभी परिवारों को प्रदान की जाएगी, सिवा उनके जिनके घरों में कम से कम एक कर देने वाला सदस्य (42.30 लाख) है अथवा वे 2 हेक्टेयर (2.8 लाख) से अधिक भूमि के मालिक हैं। योजना का बजट परिव्यय लगभग 12,900 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा

2. प्रमुख विकासात्मक मापदंडों पर चिह्नित पिछड़े समुदायों या भौगोलिक क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए तैयार किये गए हस्तक्षेप के लिए विशेष कार्यबल

मंडल आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समुदायों जैसे माहिष्य, तिली, तामुल तथा साहा को ओबीसी में शामिल करने की जांच और इसकी सिफारिश करने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही मालदा जिले के कुछ हिस्सों में अनुसूचित जनजाति के रूप में रहने वाले किसान जाति की मांगों को पूर्ति को हम सुनिश्चित करेंगे। हम महतो समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ आक्रामक रवैया अपनाएंगे।

3. लाख नये स्व सहायता समूह (एसएचजी) को किफायती ऋण

एक नयी योजना **'मातृ वंदना'** के तहत समाज की निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के साथ 10 लाख नये एसएचजी बनाए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में बैंकों के माध्यम से आसान पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ उन्हें 25,000 करोड़ रुपये के किफायती ऋण प्रदान किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त **बांग्ला मोदेर गर्व** नामक तीन दिवसीय कार्यक्रम कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए स्व-सहायता समूहों, कारीगरों, लोक कलाकारों के लिए आर्थिक अवसर उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक जिले में आयोजित किये जाएंगे

4. बेहतर शिक्षा तक पहुंच के लिए नये स्कूल खोलना

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब बच्चों को लाभान्वित करने के लिए राज्य भर में 100 नये अंग्रेजी माध्यम के अलचिकी भाषा में पढ़ाई करने के लिए स्कूल

खोले जाएंगे, जिनमें 1500 पैरा शिक्षक नियुक्त किये जाएंगे साथ ही इसके अतिरिक्त सदरी भाषा में पढ़ाई के लिए 100 नये स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 300 पैरा शिक्षक बहाल किये जाएंगे। नेपाली, हिन्दी, उर्दू, कामतापुरी तथा कुरुमाली भाषा में पढ़ाई के लिए 100 नये स्कूलों में 300 पैरा शिक्षक बहाल किये जाएंगे। सरकार द्वारा राजबंशी भाषा में पढ़ाने वाले 200 स्कूलों को मान्यता तथा आर्थिक सहायता दी जाएगी।

5. चायबागानों तथा चायबागान के श्रमिकों के लिए विशेष कार्य योजना

हम अगले दो वर्षों में चाय सुंदरी परियोजना को पूरा कर 3 लाख से अधिक स्थायी चाय बागान श्रमिकों के लिए पक्के आवास की व्यवस्था करेंगे। हम अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ीतथा दार्जिलिंग के मैदानी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों की तकलीफों को दूर करेंगे। 23 संकटग्रस्त चायबागानों को चायबागान पुनरुद्धार परियोजना में शामिल किया जाएगा।

6. मॉडल नंदीग्राम का निर्माण

नंदीग्राम को एक मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से जुड़ी सड़कें, 24x7 सस्ती बिजली और सभी के लिए पीने के पानी की आपूर्ति होगी। इसके साथ ही युवाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए एक नयी यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी

7. राष्ट्र निर्माण में देशनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को सम्मानित करने के लिए नेताजी का स्मारक बनाया जाएगा

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए न्यू टाउन, कोलकाता में आजाद हिंद स्मारक बनाया जाएगा, प्रत्येक जिले में जय हिंद भवन का निर्माण किया जाएगा, कोलकाता पुलिस में नेताजी बटालियन नामक एक बटालियन बनाई जाएगी और साथ ही **'नेताजी राज्य योजना'** आयोगफ का गठन किया जाएगा

8. घाटाल मास्टर प्लान बाढ़ प्रबंधन योजना का समापन

हालांकि भारत सरकार की ओर से घाटाल मास्टर प्लान फ्लड मैनेजमेंट स्कीम के लिए कोई फंड उपलब्ध नहीं किया गया था, लेकिन नदी के 19 किमी के पुनर्जीवन का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है और 84 किमी के लिए पहल की जा चुकी है। पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में नदी पुनर्जीवन की प्रस्तावित योजना की लंबाई कुल 147 किमी है।

युवा

अर्थिक सुअवसर, सबल युवा

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी सुयोग्य छात्रों के लिए 4% की ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक की क्रेडिट सीमा के साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की नयी योजना

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

शिक्षा और कौशल विकास

» 30 नये विश्वविद्यालय और 51 नये कॉलेज साथ ही 78 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 36 नये पॉलिटेक्निक खोले गए

रोजगार सृजन और सहायता

» 1.35 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली लगभग 9 मिलियन एमएसएमई इकाइयों (2012 की तुलना में 34.6 लाख) के साथ हमने भारत में लघु और सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई) में पहला रैंक हासिल किया है, जो रोजगार-उत्पादन में हमारी क्षमता का उदाहरण पेश करता है।

» बेरोजगार युवाओं का **युवाश्री** के तहत सहायता के स्वरूप 1500/- प्रति माह की सहायता दी गयी है, इससे बंगाल के लगभग 1,81,477 युवाओं को लाभ मिला है

» **बांग्ला स्वनिर्भर कर्मस्थान प्रकल्प** ने 2,84,000 से अधिक लोगों को उद्योग, व्यापार सेवाओं आदि की व्यवहार्य इकाई को स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसरों के साथ लाभान्वित किया है

» 1,16,865 शहरी युवाओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे सफलतापूर्वक या तो वेतनभोगी के तौर पर अथवा स्वरोजगार में लगे हुए हैं

» 4 लाख पद जो पुलिस और प्रशासन में 2011 से रिक्त पड़े थे, वे भरे गए हैं

» **स्वरोजगार ऋण:** स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करने की दृष्टि से व्यक्तिगत उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को ऋण और डीएलएस (माइक्रो फाइनेंस) प्रदान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को 2011-18 के दौरान स्थायी रोजगार के लिए 9.43 लाख रुपये का टर्म लोन और माइक्रो क्रेडिट प्रदान किये गए हैं

» **खेल :** खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में विभाग से 12460 क्लबों को अनुदान दिया गया

» वित्त वर्ष 2018-19 के बाद एक नयी योजना खेल कोचिंग शिविर का सुदृढ़ीकरण शुरू की गयी तथा पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर कोचिंग कैंपों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया गया। 475 कोचिंग कैंपों को मंजूरी दी गयी है, प्रत्येक कोचिंग कैंप को प्रतिभा की तलाश के तथा जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1-1 लाख रुपये दिए गए हैं

आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्य वादे

1. सभी सुयोग्य छात्रों के लिए 4% के ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक की क्रेडिट सीमा के साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र 4% की रियायती दर पर 10 लाख रुपये तक का क्रेडिट प्राप्त करने के पात्र होंगे। एकमुश्त लिए जाने वाले ऋण के विपरीत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से अधिक छात्रों को उनकी सुविधानुसार पैसे प्रदान करेगा।

2. सरकारी विभागों में 10,000 इंटर्नशिप के अवसर

युवाशक्ति नामक नयी योजना के तहत हर तीन साल में 10,000 छात्रों को विभिन्न सरकारी विभागों में इंटर्नशिप और पोस्ट- इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किये जाएंगे।

3. 1.1 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए विशेष पहल

अगले 3 वर्षों में राज्य द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों और पुलिस प्रणालियों में 1.1 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे

4. आईएएस/आईपीएस की परीक्षाओं के लिए 100 छात्रों को मुफ्त कोचिंग

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में विशेष प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आईएएस, आईपीएस परीक्षाओं के लिए एक सौ छात्रों को निःशुल्क भोजन, आवास और मासिक वजीफा के अतिरिक्त प्रावधानों के साथ मुफ्त कोचिंग प्रदान करने की व्यवस्था

Pepe
JEANS

आहार

बंगाल में सबके लिए निश्चित आहार

मुख्य लक्ष्य

- खाद्य साथी के तहत नयी सुविधा - अब राशन की दुकानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। 1.5 करोड़ परिवारों को मासिक राशन की मुफ्त डोरस्टेप डिलीवरी
- पचास शहरों में 2500 मां कैंटीनों द्वारा सब्सिडी युक्त 5 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति थाली आहार का प्रबंध

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

खाद्य साथी

» 2016 में 500 वितरकों और 20,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से हाशिए पर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अत्यधिक रियायती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए **खाद्य साथी योजना** की शुरुआत की गयी थी

» कोविड-19 के दौरान अनियोजित लॉकडाउन के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए खाद्य साथी योजना के तहत सभी लाभार्थियों को महामारी के दौरान **मुफ्त खाद्यान्न** प्रदान किया गया। इस पहल को जून, 2021 तक बढ़ाया गया था

» इसके अलावा, **4.85 लाख खाद्य साथी स्पेशल कूपन** लोगों को जारी किये गए थे, जिनके पास वर्तमान में डिजिटल राशन कार्ड नहीं हैं। इस योजना से **10 करोड़** लोग लाभान्वित हुए हैं

» इसके अलावा, **45.89 लाख प्रवासी और फंसे हुए मजदूरों को** अस्थायी तौर पर खाद्य कूपन प्रदान किये गए और 45894 मीट्रिक टन चावल और 2655 मीट्रिक टन चना भी वितरित किया गया

» यह सुनिश्चित करने के लिए कि संकट के समय कोई व्यक्ति छूट नहीं जाए, एक विशेष अभियान चलाया गया और **यौनकर्मियों तथा ट्रांसजेंडरों** को डिजिटल राशन कार्ड और **खाद्य साथी विशेष कूपन** प्रदान किये गए

खरीद और भंडारण सुविधाओं का विस्तार

» राज्य में 349 सरकार द्वारा संचालित केंद्रीकृत खरीद केंद्र (सीपीसी) और 1098 सहकारी समितियां, खाद्य उत्पादक संगठन और स्व-सहायता समूह हैं।

» किसानों के लिए अपना पंजीकरण करने और धान बेचने के लिए एक आसान और सुविधाजनक मोबाइल एप **खाद्य साथी अन्नदात्री एप** को लॉन्च किया गया है

» राज्य के अधिकांश लोगों के लिए चावल के मुख्य आहार का हिस्सा होने के कारण चावल की भंडारण क्षमता को **10 लाख मीट्रिक टन** तक बढ़ाया गया है, जो 2011 में केवल 63,000 मीट्रिक टन था

सब्सिडाइज्ड फूड कैंटीन

» रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने की **एकुशे अन्नपूर्णा योजना** की कामयाबी के बाद **मां योजना** फरवरी, 2021 में शुरू की गयी। पके हुए भोजन में चावल, दाल, सब्जियां शामिल होती हैं इसके अलावा अंडा करी के साथ पूरे राज्य में 27 **मां कैंटीन** द्वारा सब्सिडी युक्त भोजन 5 रुपये प्रति थाली प्रदान किया जाता है

आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्य वादे

1. खाद्य साथी योजना की नयी सुविधाः राशन दुकानों तक जाने की कहीं जरूरत नहीं, 1.5 करोड़ परिवारों को मासिक राशन की मुफ्त डोरस्टेप डिलीवरी

पश्चिम बंगाल के लोगों की औसत पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए समर्पित कर्मियों के माध्यम से खाद्यान्न की मुफ्त डिलीवरी तथा जमीनी स्तर पर राशन का पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करेगा। राज्य अगले पांच वर्षों तक हर महीने उचित मूल्य की दुकानों से लगभग 1.5 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने का लक्ष्य रखेगा।

2. 50 शहरों में 2500 मां कैंटीनों के माध्यम से 5 रुपये प्रति थाली 75 करोड़ सब्सिडी युक्त भोजन

'मां कैंटीन' का उद्देश्य शहरी गरीबों को 5 रुपये प्रति भोजन की थाली की रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना होगा। 75 करोड़ सब्सिडी वाले भोजन उपलब्ध कराने के लिए 50 शहरों में 2,500 मां कैंटीन स्थापित की जाएंगी

3. सभी 10 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन

कोविड -19 के दौरान आए संकट के कारण सरकार 30 जून 2021 तक सभी नागरिकों को मुफ्त राशन दे रही थी। हालांकि, अब इस मुफ्त राशन को जून, 2021 के बाद भी अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 1,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जारी रखा जाएगा

खेती-बाड़ी और कृषि

उत्पादन में वृद्धि, सुखी किसान

मुख्य लक्ष्य

- कृषक बंधु योजना के तहत 68 लाख लघु और सीमांत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता प्रदान की जाएगी
- कुल सिंचाई क्षेत्र और फसल के घनत्व में नंबर 1 राज्य होने के लिए और 3 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को खेती-बाड़ी में शामिल कर और 4.5 लाख हेक्टेयर को दोहरे फसल प्रणाली में परिवर्तित किया गया है
- खाद्यान्न और चार नकदी फसलों के लिए उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में स्थान - चाय, जूट, आलू और तम्बाकू

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

» कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2011 तुलना में व्यय में 6.1 गुना वृद्धि हुई है। यह 2010-11 में 3029.39 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 18603.00 करोड़ हो गयी है

» 2010-11 में खाद्यान्न उत्पादन 148.10 एलएमटी से बढ़कर 2019-20 में 198.65 एलएमटी हो गया है, धान का उत्पादन 2010-11 में 133.9 एलएमटी से बढ़कर 2019-20 में 165.03 एलएमटी हो गया है, मक्का का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से 2016-17 में 4.6 टन/ हेक्टेयर से बढ़कर 6.80 टन/ हेक्टेयर हो गया और दालों का उत्पादन 2010-11 में 1.77 एलएमटी से बढ़कर 2019-20 में 3.93 एलएमटी हो गया।

» 2020-21 के दौरान पश्चिम बंगाल में 30.12.2020 तक 12.90 लाख मीट्रिक टन मछली और 24875 मिलियन मछली के बीज का उत्पादन दिसंबर, 2020 तक किया गया है

» वार्षिक अंडे का उत्पादन 2010-11 में 400.1 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 973.5 करोड़ हो गया, यानी नौ वर्षों में 143.31% की वृद्धि, मांस उत्पादन में 56.5% की वृद्धि और दूध का उत्पादन 33.45% बढ़ा

» **सुफला बांग्ला** परियोजना 2014 में शुरू की गयी, वर्तमान में राज्य भर में 331 रिटेल आउटलेट, 63 मोबाइल वैन तथा 3 हब के साथ यह योजना चल रही है। सुफला बांग्ला आउटलेट के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 75-80 मीट्रिक टन कृषि उपज 18 से 20 लाख रुपये प्रतिदिन बिकती है और यह 2.00 -2.50 लाख उपभोक्ताओं को रोजाना सेवाएं प्रदान करती है

» पश्चिम बंगाल वर्ष 2017-18 के दौरान मोटे अनाज उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लगातार 6वें वर्ष के लिए **कृषि कर्मण पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है

» **कृषक बंधु** के तहत- जनवरी 2019 में किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गयी तथा 46.76 लाख किसानों तक 2,647.89 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया गया है। 16,563 मृत किसानों के परिवार के सदस्यों को मृत्यु लाभ प्रदान किया गया है

» अन्न के भंडारण की सुविधा के साथ 186 किसान मंडियों का निर्माण किया गया है ताकि स्थानीय किसानों के लिए उत्पादों की बिक्री को आसान किया जा सके

» **आमार फसल आमार गोला :** कटाई के बाद फसल के नुकसान को रोकने के लिए और फसल उत्पाद के स्तर को बढ़ाने के साथ इसके अतिरिक्त एक बार की सहायता के तहत आमार फसल आमार गोला के माध्यम से 17,975 रुपये प्रदान किये जाते हैं, जिससे कि उन्नत कम लागत वाले धान और अनाज के भंडारण की संरचनाओं के निर्माण के लिए गोला और आधे उबले धान (उसीना) को धूप में सूखने के लिए धान प्रसंस्करण गोला के निर्माण के लिए 5,000 रुपये दिये जाते हैं

» सन् 2011 में 20 लाख से लेकर 2020 तक कुल 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए हैं, जिनके अतिरिक्त 20 लाख कार्ड वितरित किए जाने की प्रक्रिया में हैं

» सरकार प्रदान करती है- **किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना** के तहत 1,000 रुपये का मासिक पेंशन लगभग 1 लाख लोगों को प्रदान किया जा रहा है

- पूरी तरह से राज्य पोषित फसल बीमा **बांग्ला शस्य बीमा योजना** के तहत 2020 के खरीफ की फसल के दौरान 64 लाख किसानों के 22.55 लाख हेक्टेयर भूमि का इस योजना के तहत बीमा किया गया
- **माटीर सृष्टि:** राज्य के पश्चिमी भाग में 6 जिले बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम और पश्चिम बर्दवान में परती भूमि का उत्पादक उपयोग करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। पिछले साल यह परियोजना 1,942 स्थानों में 13,000 एकड़ जमीन पर लॉन्च की गयी थी। इस वर्ष 14,000 एकड़ भूमि का और परिवर्तन किया जाएगा, जिससे कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि में रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे
- वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 409.36 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है। 31,285 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के अतिरिक्त क्षेत्र में शामिल किया गया है ताकि 2,21,127 किसानों को इसका लाभ मिल सके
- 30,845 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 14,472 हेक्टेयर कृषि भूमि पर स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को चालू किया गया। दोनों की स्थापना के साथ दिसंबर, 2020 तक अतिरिक्त 5,787 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की क्षमता बढ़ाई जाएगी
- जमीन की लीजिंग, म्यूटेशन और कन्वर्जन जैसी सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम चालू किया गया है। ई-धान खरीद प्रणाली के तहत 21.45 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है
- पश्चिम बंगाल राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने राज्य में कृषि उपज के तीव्र और परेशानी मुक्त लेन-देन के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिंगल प्लेटफॉर्म परमिट (ई-परमिट) की व्यवस्था शुरू की है

आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्य वादे

1. **कृषक बंधु योजना के तहत 68 लाख लघु और सीमांत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता प्रदान की जाएगी**

   पश्चिम बंगाल में इस समय 71.23 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें से 96% छोटे और सीमांत किसान हैं। पश्चिम बंगाल में भूमिजोत का औसत आकार 0.77 हेक्टेयर है। राज्य के 68.38 लाख लघु और सीमांत किसानों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

2. **राज्य के नंबर 1 होने के लिए कुल बुआई के क्षेत्र में और फसल के घनत्व में 3 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जोड़ने के अतिरिक्त और 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को दोहरी फसल प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा।**

   पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 93% शुद्ध बुआई के क्षेत्र के साथ (बड़े राज्यों में) नंबर 2 पर है और पंजाब इस सूची (97%) में शीर्ष स्थान पर है। अगले पांच साल में राज्य में कुल बुआई के क्षेत्र में 98% की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त 3 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को खेती के दायरे में लाकर यह राज्य कुल बुआई के क्षेत्र में नंबर 1 बन जाएगा। पश्चिम बंगाल बड़े राज्यों में 182% (2011-16) की औसत फसल घनत्व के साथ तीसरे स्थान पर है, जिसमें पंजाब और हरियाणा शीर्ष 2 राज्य हैं। अतिरिक्त 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को दो फसली प्रणाली में परिवर्तित कर पश्चिम बंगाल फसल घनत्व में रैंक 1 प्राप्त करेगा

3. **खाद्यान्न और चार नकदी फसलों के लिए उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में होगा- चाय, जूट, आलू और तम्बाकू**

   पश्चिम बंगाल वर्तमान में चाय (2,076 किलोग्राम / हेक्टेयर), जूट (2,617 किलोग्राम/ हेक्टेयर) और आलू (29,901 किलोग्राम/ हेक्टेयर) के उत्पादन के साथ पहले स्थान पर है। राज्य में तम्बाकू (1,263 किलोग्राम/ हेक्टेयर) और खाद्यान्न (2,856 किलोग्राम/ हेक्टेयर) के साथ उत्पादन से छठे स्थान पर है। अगले पांच वर्षों में राज्य चाय, जूट और आलू में पहली रैंक बरकरार रखते हुए खाद्यान्न और तम्बाकू के उत्पादन में अपनी रैंक में सुधार करेगा

4. **प्रत्येक जिले में मेगा/ मिनी फूड पार्क की स्थापना**

   कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रत्येक जिले में फसल- विशिष्ट मेगा/ मिनी फूड पार्क स्थापित करेगी साथ ही कोल्ड चेन और गुणवत्ता जांच सुविधाएं मुहैया करायेगी

5. **कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा**

   कृषि यंत्रीकरण द्वारा कृषि उपज बढ़ाने के लिए विभिन्न सहकारी समितियों में फार्म मशीनरी हब (कस्टम हायरिंग सेंटर) स्थापित किए जाएंगे। अब तक 379 सहकारी

समितियों को इसके लिए 108.70 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है

6. संबद्ध सेवाओं के विकास को बढ़ावा देना

स्वयं सहायता समूहों की सहायता से मछली तलने से लेकर मछली के बीज नामक नयी योजना शुरू की जाएगी। ऐसी दो इकाइयां प्रति ब्लॉक में शुरू की जाएंगी और स्वयं सहायता समूहों द्वारा पोषित मछली के बीजों को वापस लिया जाएगा और स्वयं सहायता समूहों को सुनिश्चित बढ़ी आय प्रदान करने के लिए पहले वर्ष में विभाग द्वारा पाले जाने के लिए अन्य स्वयं सहायता समूहों को वितरित किया जाएगा

बागवानी गतिविधियों के तहत सेब जैसे गैर-पारंपरिक फलों की बागवानी की शुरुआत के अतिरिक्त हेजलनट, अखरोट, ब्लूबेरी, रसभरी, आड़, नाशपाती, बेर, कीवी, अनार, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो आदि फलों का विकास और बागवानी। मशरूम, रबर प्रसंस्करण, आवश्यक तेलों की पेराई, फलों और औषधीय पौधों की फसल के बाद इनके प्रसंस्करण तथा उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास

उद्योग

शिल्पोन्नत बंगाल

मुख्य लक्ष्य

- कार्यशील एमएसएमई इकाइयों की कुल संख्या को बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने के लिए हर साल इनमें अतिरिक्त 10 लाख एमएसएमई इकाइयां जोड़ी जाएंगी
- 2000 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को अगले 5 साल में 10,000 इकाइयों के मौजूदा आधार में जोड़ा जाएगा
- अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये का नया निवेश

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

» देश के कुल एमएसएमई में राज्य के लगभग 89 लाख एमएसएमई की करीब 14% भागीदारी है। एमएसएमई पिछले 9 वर्षों में 11% सीएजीआर की दर से आगे बढ़े हैं जिससे देश में राज्य रैंक 1 पर बना हुआ है

» पश्चिम बंगाल 23.42% हिस्सेदारी के साथ भारत में कुल महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के संबंध में अग्रणी है

» 2010 में बंगाल में फैक्टरियों की संख्या 8,322 से सन् 2020 में बढ़कर 9,534 (15%) हो गयी तथा औसत फैक्टरी वर्कर की कमाई 1.3 लाख से बढ़कर 2.3 लाख (77%) रुपये हो गयी है

» **बंगाल सिलिकॉन वैली परियोजना:** 100 + एकड़ जमीन भूखंड 20 से अधिक संस्थानों को आवंटित किये गये हैं, जो लगभग 11,317 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए बड़े अवसर होंगे

» **देवचा पचमी** दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है, जिसमें अनुमानित 2.1 बिलियन टन कोयले का भंडार है। बीरभूम जिले में देवचा पचमी कोयला ब्लॉक के परिचालन के बाद एक लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे

» **ताजपुर में सी पोर्ट** 15,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में लगभग 25,000 नौकरियां उत्पन्न करेगा

» **रूरल क्राफ्ट एंड कल्चरल हब (आरसीएच):** इस विशेष पहल के तहत यूनेस्को और राज्य सरकार परस्पर सहयोग कर कई पहल के माध्यम से बंगाल के पारम्परिक और विरासत उत्पादों को बढ़ावा देने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए इस परियोजना में साथ जुड़े हैं। यह पहले की ग्रामीण शिल्प हब परियोजना का विस्तार है और इसमें 50,000 कलाकार शामिल किये जाएंगे

» **क्लस्टर विकास के तहत सामान्य सुविधाएं :** क्लस्टर के हितधारक समूहों का विकास और उन्हें आवश्यक सामान्य सुविधाएं प्रदान करना विभाग का प्रमुख उद्देश्य है। अब तक, एमएसएमई, हैंडलूम और ग्रामोद्योग समूहों के लिए 9 कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किये गए हैं।

» **हथकरघा बुनकरों के लिए हित अनुदान योजना :** हथकरघा बुनकरों को कार्यशील पूंजी सहायता की सुविधा प्रदान करने तथा बुनकरों के ऋण के वास्तविक बोझ को प्रभावी ढंग से घटाकर केवल 2% करने के लिए विशेष पहल शुरू की गयी है।

आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्य वादे

1. कार्यशील एमएसएमई इकाइयों की कुल संख्या को बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने के लिए हर साल अतिरिक्त 10 लाख एमएसएमई जोड़े जाएंगे।

एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार, पश्चिम बंगाल में एमएसएमई की संख्या 2006-07 में 34.64 लाख से बढ़कर 2015-16 में 88.67 लाख (एनएसएस 73 वें दौर, 2015-16) में एक साल में 11% की साल दर साल वृद्धि दर रही है। पिछले 9 साल में हर साल औसतन 6 लाख एमएसएमई यूनिट्स जोड़ी गईं हैं। उद्योगीकरण का लाभ आम जनता तक ले जाते हुए और विकेंद्रीकृत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार अगले पांच वर्षों के लिए हर साल एमएसएमई की संख्या को बढ़ाकर 10 लाख करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह संख्या 1.5 करोड़ तक पहुंच सके।

2. अगले 5 वर्षों में 10,000 इकाइयों के मौजूदा आधार में 2000 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा जाएगा

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कारखानों की संख्या वर्ष 2010-11 में 8,232 थी, जो 2017-18 में बढ़कर 9,534 हो गयी, जिसमें 65 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। तेज गति से औद्योगिकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की कुल संख्या को बढ़ाकर 12,000 इकाइयों से अधिक कर दिया जाएगा।

3. अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये का नया निवेश

पिछले पांच वर्षों में राज्य को पांच वैश्विक शिखर सम्मेलनों से बड़े उद्योग में 4.45 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ। हम राज्य में आयोजित वार्षिक वैश्विक शिखर सम्मेलन से आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश लाएंगे

पश्चिम बंगाल में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आईटी और बीटी कंपनियों को आकर्षित करने के कदम उठाए जाएंगे

4. औद्योगिक क्षेत्र में डिजिटल क्रांति

राज्य में समस्त औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्रांति लाने हेतु महत्वाकांक्षी सिद्धांतों और कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा

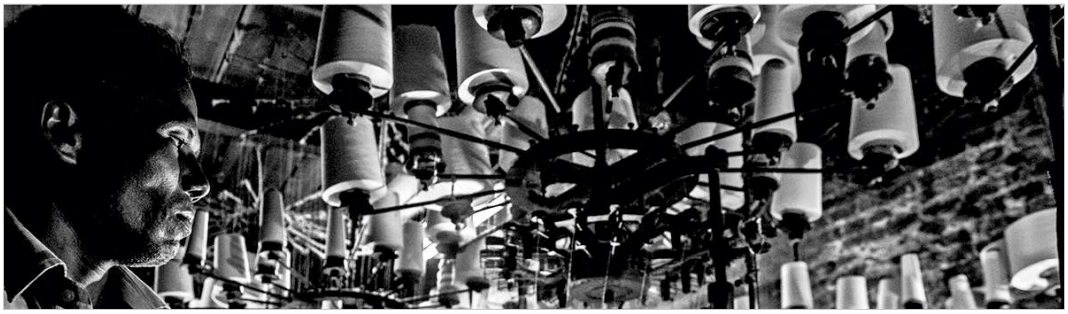

स्वास्थ्य

उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वस्थ बंगाल

मुख्य लक्ष्य

- स्वास्थ्य पर व्यय 0.83% से बढ़ाकर इसे दोगुना, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% करना है
- सभी 23 जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज- सह -सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
- डॉक्टरों, नर्सों, और सहयोगी स्टाफ के लिए सीटों की संख्या दोगुनी करना

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

सभी के लिए समावेशी स्वास्थ्य

» 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली योजना **स्वास्थ्य साथी** में 1.94 करोड़ से अधिक परिवारों (करीब 10 करोड़ लोगों) को शामिल किया गया है।

» स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए बजट में तीन गुना से अधिक वृद्धि की गयी है। सन् 2010 में 3,442 करोड़ रुपये के आवंटन से बढ़ाकर इसे सन् 2020 में 11,280 करोड़ रुपये किया गया है

» गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं के लिए राज्य में 1000 उन्नत **मातृयान एंबुलेंस** उनकी यात्राओं और उनके स्थानांतरण के लिए शुरू की गयी है

» कोविड-19 रोगियों का उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने 102 समर्पित कोविड अस्पताल मुहैया किये जिनमें 13,588 ऑक्सीजन बेड और 2,523 सीसीयू / एचडीयू बेड वाले अस्पताल और 57 निजी अस्पताल भी शामिल किये गए

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) और डायग्नोस्टिक सेवाएं

» राज्य में पूरी तरह से कार्यशील सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की 41 इकाइयां और 72 क्रिटिकल केयर सुविधाएं हैं, जिनमें 1,90,000 से अधिक लोगों को गुणवत्ता पूर्ण क्रिटिकल केयर उपचार प्राप्त हुआ है

» 152 उच्च और उचित मूल्य नैदानिक केंद्र डायलिसिस की सुविधा के साथ स्थापित किये गए हैं जहां 96.44 लाख मरीज निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं

» 5 अलग स्वास्थ्य जिलों का गठन किया गया है यथा बसीरहाट, डायमंड हार्बर, रामपुरहाट, बिष्णुपुर और नंदीग्राम

» **शिशु साथी प्रकल्प** के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क हृदय ऑपरेशन की व्यवस्था

अस्पताल के बिस्तरों, डॉक्टर्स और नर्सों की संख्या में वृद्धि

» पिछले 10 सालों में सरकारी अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 58,647 से बढ़ाकर 85,627 की गयी है, जो 46% की बढ़ोतरी दर्ज करती है। देशभर के सरकारी अस्पतालों में बंगाल में सबसे अधिक बिस्तरों की संख्या है

» डॉक्टरों की संख्या 4,800 से बढ़ाकर 15,338 की गयी है और नर्सों की संख्या 37,366 से बढ़ाकर 56,589 की गयी है

» 2011 में प्रोत्साहन- वेतन के रूप में अधिकतम 1500 रुपये से आशा कार्यकर्ताओं की आय अब लगभग 6500 (मानदेय 3500 रुपये+ 3000 रुपये प्रोत्साहन) रुपये प्रति माह हो गयी है।

आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्य वादे

1. स्वास्थ्य मद में व्यय को 0.83% से दोगुना कर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 1.5% तक करना

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य के मद में 12,561 करोड़ रुपये खर्च करता है, जो इसके जीएसडीपी का 0.83% है और भारतीय राज्यों के बीच स्वास्थ्य बजट के आवंटन के मामले में राज्य 10वें स्थान पर है। वर्तमान बजट परिव्यय में 5,500 करोड़ रुपये की औसत वार्षिक वृद्धि के कारण राज्य को 2026 तक जीएसडीपी का 1.5% खर्च करने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

2. सभी 23 जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज -सह -सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

पश्चिम बंगाल में 18 सरकारी मेडिकल कॉलेज-सह-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं, जिनमें 5 कोलकाता में हैं। इसके अलावा हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, झारग्राम और उत्तर 24 परगना में 5 और कॉलेजों को मंजूरी दी गयी है। सरकार का लक्ष्य इन पांच जिलों में 5 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण करना है, जहां वर्तमान में ऐसी सुविधाओं का अभाव है

3. डॉक्टर्स, नर्सों, और सहयोगी स्टाफ के लिए सीटों की संख्या दोगुनी करना

राज्य में वर्तमान में प्रति 10,000 की आबादी पर क्रमशः 15 डॉक्टरों और 10 नर्सों का अनुपात है। यह 13.4 (एनसीबीआई) के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्तमान में नर्सिंग कॉलेजों में 6,362 सीटें हैं, मेडिकल कॉलेज में 2,850 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स, नर्सों और सहयोगी स्टाफ के लिए सीटों की संख्या दोगुनी की जाएगी

शिक्षा

आगे बढ़ते रहने के लिए शिक्षित बांग्ला

मुख्य लक्ष्य

- शिक्षा पर व्यय को राज्य के जीडीपी का 2.7 फीसदी से 4 फीसदी किया जाना
- प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक मॉडल आवासीय स्कूल
- शिक्षकों के प्रशिक्षण की सीट की संख्या को बढ़ा कर दोगुना किया जाना

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

शिक्षा पर राज्य सरकार का व्यय

» पिछले 10 वर्षों में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि जो 2010-11 के 13,872 करोड़ रुपए से बढ़ कर 2020-21 में 37,059 करोड़ रुपए हो गया।

बचपन में प्राथमिक शिक्षा

» **शिशु आलोय,** बचपन के शुरुआती दौर में शैक्षिक पाठ्यक्रम चल रहा है राज्य के 53,894 केंद्रों में।

» घर पर रहने को बाध्य 3-6 वर्ष के 22.28 लाख बच्चों ने मोबाइल ऐप पर आधारित पहल का लाभ उठाया और इस तरह उन्हें कोविड-19 पैनडेमिक के दौरान प्री स्कूल शिक्षा सेवाएं सुनिश्चित की गईं। इस पहल को गोल्ड **स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड 2020** मिला है।

स्कूली शिक्षा

» बढ़ते हुए विद्यार्थियों की संख्या को समायोजित करने के लिए 2010 से 95,378 नयी स्कूली कक्षाओं का निर्माण कराया गया।

» **सबूज साथी योजना** के तहत एक करोड़ से भी विद्यार्थियों को साइकिलें दी गईं और इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ का सम्मानित **डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार** मिला है।

» **कन्याश्री प्रकल्प** ने 70 लाख से अधिक लड़कियों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। कन्याश्री ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है

» **मिड डे मिल प्रोग्राम** में 1.13 करोड़ विद्यार्थियों को भोजन दिया गया। इसके अतिरिक्त 92 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दिया गया।

» प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को 2020 में मुफ्त में टेक्स्ट बुक दी गई।

» ई-लर्निंग मोड तक पहुंच के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों को टैब व स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए **तरुणेर स्वप्न** के तहत दिए गए।

उच्च शिक्षा

» सरकार द्वारा 30 नये विश्वविद्यालय और 51 कालेजों का निर्माण कराये जाने के कारण दाखिला लेने वालों की औसत संख्या पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई।

» लड़कियों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 4 पूरी तरह नयी गर्ल्स गवर्नमेंट कालेजों का उद्घाटन किया गया।

» **स्वामी विवेकानन्द मेरिट कॉम मीन्स स्कालरशिप स्कीम** के तहत 1.35 लाख वंचित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कालरशिप दी गई।

तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास

» पोलिटेक्निक में प्रवेश की संख्या 2011 में 17,185 थी जो 2020 में दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 39,835 हो गई।

» **पश्चिम बंग सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट** के तहत 9 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों को शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट इंटरवेंशन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

» **उत्कर्ष बांग्ला स्कीम** के तहत 2016 से 20 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया।

आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्य वादे

1. शिक्षा पर व्यय को राज्य के जीडीपी के 2.7 फीसदी से बढ़ा कर 4 फीसदी किया जाएगा

भारतीय राज्यों में शिक्षा के लिए बजट के आवंटन के मामले में पश्चिम बंगाल 10वें स्थान पर है। शीर्ष 5 रैंकिंग में स्थान पाने तथा राज्य की सुविधाओं में सुधार जारी रखने के लिए बजटीय आवंटन 4% तक बढ़ाया जाएगा

2. प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक मॉडल रेसिडेंसियल स्कूल

सरकार का लक्ष्य सभी 341 ब्लॉकों में कक्षा 6 से 12 तक के लिए टेक्नॉलाजी से समृद्ध मॉडल रेसिडेंसियल स्कूल की स्थापना करने की है। इन स्कूलों में डिजिटल क्लास रूम, लाइब्रेरी और पाठ्यक्रम जैसी स्टेट ऑफ आर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं होंगी।

3. अध्यापकों के प्रशिक्षण के सीटों की संख्या को दोगुनी करना

पश्चिम बंगाल में वर्तमान में बी एड कालेजों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 33,095 सीट हैं और छात्र-अध्यापक प्रतिशत 2016-17 का 21:1 है। सरकार टीचिंग प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ा कर 62,000 करेगी और इससे विद्यार्थियों का तेजी से, समतुल्य और सामूहिक विकास होगा।

4. कन्याश्री योजना का उच्च शिक्षा और रोजगार की दिशा में विस्तार

सरकार की योजना है कि वर्तमान की कन्याश्री योजना का विस्तार किया जाए ताकि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार का अवसर पाने में मदद की जा सके। इस योजना को कन्याश्री प्लस नाम दिया जाएगा।

5. तरुणेर स्वप्न योजना के तहत बारहवीं कक्षा के 9 लाख छात्रों को टैबलेट प्रदान करना

बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले 9 लाख छात्रों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु टैब प्रदान करने के लिए हर साल तरुणेर स्वप्न योजना जारी रखी जाएगी

6. पैराटीचरों की पारिश्रमिक में वृद्धि और 3 लाख रुपए की सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाना

सरकार का प्रस्ताव है कि पैराटीचरों को सालाना 3 फीसदी वृद्धि दी जाए। इसके अलावा 60 साल होने पर एकमुश्त 3 लाख रुपए सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में दिए जाएं।

7. पश्चिम बंग सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट (पीबीएसएसडी) स्कीम के तहत दाखिले में वृद्धि

रिकगनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) मोड के तहत 2021-22 में 1 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए पीबीएसएसडी की शुरुआत की गई थी। इसका आगे विस्तार किया जाएगा।

8. सभी 278 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स में स्मार्ट क्लासरूम का विस्तार करना।

वर्तमान में सरकार के 42 आईआईटी में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा है। इसका विस्तार सभी 278 आईटीआई में किया जाएगा। प्रवेश क्षमता बढ़ कर 86,300 हो जाएगी।

9. सभी के लिए डिजिटल शिक्षा

पश्चिम बंगाल के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में प्रत्येक छात्र, शिक्षक को डिजिटल रूप से समृद्ध शिक्षा प्रदान की जाएगी

10. सभी प्रमुख भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री

राज्य में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की भागीदारी के साथ बांग्ला और अन्य प्रमुख भाषाओं में रचनात्मक शैक्षणिक सामग्री विकसित की जाएगी

11. बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना

प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर आवश्यक उपाय किये जाएंगे ताकि पश्चिम बंगाल भारत में शिक्षा के सर्वोत्तम केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे। हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल में अध्ययन करने के लिए भारत और दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करना होगा

आवास

सबके सिर पर मिले छांव

मुख्य लक्ष्य

- बस्तियों की आबादी को 7 फीसदी से घटा कर 3.65 फीसदी किये जाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में बांग्ला बाड़ी स्कीम के कम मूल्य वाले 5 लाख अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे
- कच्चे मकानों की संख्या 1 फीसदी से कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बांग्ला आवास योजना के तहत कम मूल्य वाले 25 लाख अतिरिक्त मकान बनाएं जाएंगे

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

» **बांग्ला आवास योजना-** 33.7 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को 1.2 लाख रुपए दिए गए और इस पर 39,009 करोड़ रुपए की लागत आयी थी।

» **इंटिग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट-** इस योजना के तहत 49,705 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

» **निर्मल बांग्ला अभियान-** इस योजना के तहत 82.60 लाख शौचालय बनाए गए। आज बंगाल का प्रत्येक ब्लॉक और ग्राम पंचायत खुले में शौच करने की पीड़ा से मुक्त है।

» **कर्मांजलि- 14** कर्मांजलि शुरू हो गए हैं ताकि कम वेतन पाने वाली अकेली महिलाओं को किराये पर वर्किंग वीमेन हॉस्टल में रहने के लिए स्थान दिया जा सके।

» **नाइट शेल्टर्स-** मरीजों तथा उनके तीमारदारों के लिए 11 नाइट शेल्टर बनाए जाने का कार्य पूरा हो चुका है।

» **आकांक्षा हाउसिंग** स्कीम के तहत सेवारत सरकारी कर्मचारियों 576 फ्लैट दिए गए हैं।

» बंगाल को **ग्रामीण आवास** में नंबर 1 का दर्जा मिला हुआ है। 2011 से अभी तक 50 लाख मकानों का निर्माण कराया जा चुका है।

आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्य वादे

1. **शहरी आबादी में बांग्ला बाड़ी योजना के तहत 5 लाख अतिरिक्त कम लागत वाले आवास बनाया जाना, जिससे स्लम आबादी का अनुपात 7% से कम होकर 3.65% हो जाए**

   राज्य में बस्तियों की आबादी का प्रतिशत 7% है, बस्तियों की आबादी को 3.65% से नीचे लाने के लिए राज्य 27.5 लाख लोगों को आवास प्रदान करने हेतु 5 लाख घरों का निर्माण करेगा

2. **बांग्ला आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले 25 लाख अतिरिक्त मकान बनाकर कच्चे घरों का अनुपात 1% से कम करना**

   बांग्ला आवास योजना के तहत अब तक कुल 33.62 लाख घर पंजीकृत किए जा चुके हैं और 21.82 लाख घर बन चुके हैं। बंगाल में सभी के लिए एक छत सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों का अनुपात 1% से कम करने के लिए, अगले पांच वर्षों में 25 लाख कम लागत वाले पक्के मकान अतिरिक्त बनाए जाएंगे

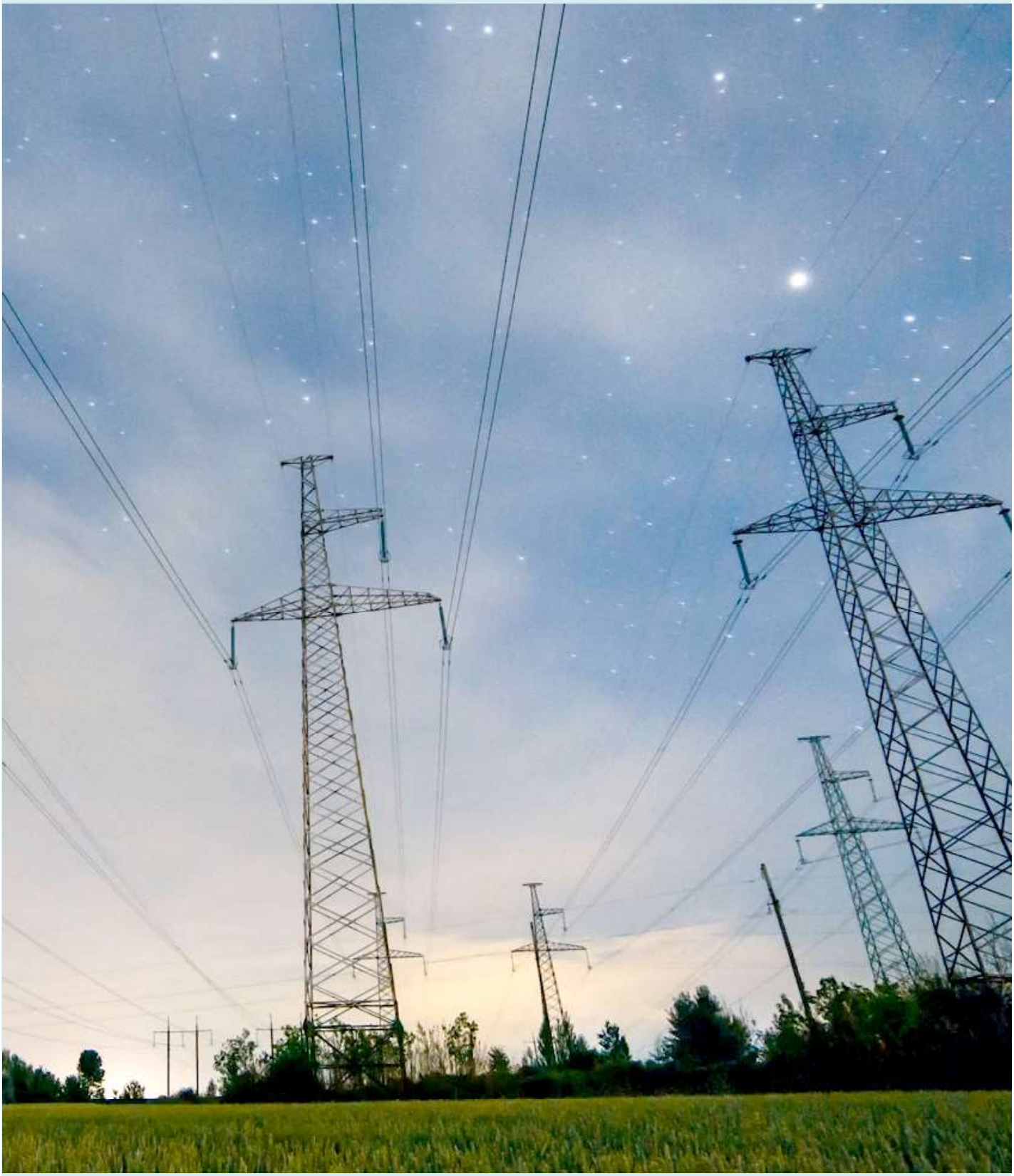

१०

बिजली, सड़क तथा पेयजल

हरेक घर को बिजली, सड़क और पेयजल

मुख्य लक्ष्य

- नगरीय क्षेत्र के 47 लाख मकानों में पाइप लाइन से पेयजल पहुंचाने की योजना ताकि 100 फीसदी के लक्ष्य की पूर्ति हो सके
- सभी घरों में वहनयोग्य दरों पर 24X7 घंटे बिजली पहुंचायी जा सके
- सभी ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों को पक्की सड़क से जोड़ना, एक कार्यशील ड्रेनेज सिस्टम और पाइप लाइन से पेयजल

पिछले 10 साल की उपलब्धियां

ऊर्जा-बिजली

» **विद्युतीकरण-** विद्युतीकरण का 100 फीसदी लक्ष्य हासिल करने के लिए 2011 से अभी तक 95.3 लाख मकानों में बिजली पहुंचायी गई।

» ग्रामीण बंगाल ने 100 फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है सभी 37,960 गांवों में बिजली पहुंचायी जा चुकी है।

» प्रति व्यक्ति खपत 2010 में 550 किलोवाट थी जो 2019 में 703 किलोवाट हो गई और इस तरह 30 फीसदी वृद्धि हुई।

» **हांसिर आलो** वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह योजना लाँच की गई ताकि मीटर किराया सहित 16.5 लाख पात्र लाभार्थियों को 25 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त में दी जाए।

सड़क

» कुल 1,18,128 किलोमीटर नयी ग्रामीण सड़कें बनायी गई और पिछले दशक में उच्चीकरण किया गया।

» **बांग्ला सड़क निर्माण योजना** पश्चिम बंगाल ने 20,000 किलोमीटर सड़क बना कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

» **बांग्लार ग्रामीण सड़क योजना** 35,611.41 किलोमीटर लंबी सड़क की मंजूरी दी गई है और इस पर 16,561.62 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

पानी

» 2011-19 के दौरान 2.25 करोड़ ग्रामीणों को पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति के साथ ही ट्यूबवेल लगाए गए जबकि 2004 से 2011 के बीच यह संख्या 15,631 थी।

» **जल धरो जल भरो-2020-21** में करीब 20,070 वाटर बॉडीज और पानी को थामे रखने के लिए ढांचे का निर्माण और पुनरोद्धार किया गया और जल संरक्षण एवं संचयन के लिए 15,597 ढांचों का निर्माण किया गया।

» 1741 लघु सिंचाई योजनाओं का, जिनकी सिंचाई क्षमता 31,952 हेक्टेयर है, का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

» **जलातीर्थ योजना** पानी की कमी से जूझ रहे पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर जिलों के लिए लांच की गई और प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्र जैसे कंसावती, दामोदर और मयूराक्षी आदि में चेकडैम का निर्माण कराया गया ताकि कटान की तीव्रता और मृदाक्षरण को रोका जा सके और निचले क्षेत्र में जलजमाव पर काबू पाया जा सके। 2020 के नवंबर तक वन क्षेत्र की 99 परियोजनाओं को कृषि योग्य बना दिया गया और इनका रकबा 2012 हेक्टेयर है।

» **आर्सेनिक मुक्त पानी** पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए पूरे साल 217 वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी काम करती हैं ताकि पानी के अंदर आर्सेनिक, फ्लूराइड, खारापन, आयरन और वैक्टरिया संक्रमण की जांच की जा सके। 2020 में 31 दिसंबर तक 1.73 लाख जल स्रोतों से 3.15 लाख नमूनों की जांच की गई।

आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्य वादे

1. अतिरिक्त 47 लाख नगरीय आवासों को पाइप लाइन से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी ताकि 100 फीसदी लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

100 फीसदी नगरीय आवासों को पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति करने के लक्ष्य के तहत 47 लाख अतिरिक्त आवासों को पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार ने अगले पांच वर्षों में 58,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ पश्चिम बंगाल में पूरे 2 करोड़ परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल स्वप्न योजना की घोषणा की है

2. 247 बिजली वहनयोग्य दरों पर सभी घरों के लिए

पश्चिम बंगाल ने 100 फीसदी विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब अगला लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बने जहां 24 घंटे 7 दिन बिजली की आपूर्ति होती हो और राज्य के सभी नागरिकों को वहन योग्य दरों पर बिजली मिले। अब राज्य की योजना है कि ऊर्जा के परंपरागत, वैकल्पिक और नवीकरणीय स्रोतों से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करे जिससे सिर्फ बिजली ही नहीं मिलेगी बल्कि यह बिजली का वहनयोग्य स्रोत भी होगा।

3. प्रत्येक ग्रामीण आवासीय क्षेत्र को पक्की सड़क से जोड़ा जाना, कार्यशील ड्रेनेज सिस्टम और पाइप के जरिए पानी की आपूर्ति

हमारी सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ आवासों को पाइप लाइन के जरिए पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में राज्य में 1,18,128 किलोमीटर नयी सड़कें बनायी है। इस प्रगति को बनाये रखते हुए अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्रामीण आवासों को पक्की सड़क से जोड़ देगी।

4. बेहतर सड़कें और सुरक्षा को देंगे प्रमुख वरीयता

अगले 5 वर्षों में पथश्री योजना के तहत 46,000 किलोमीटर नयी ग्रामीण सड़कें बनायी जाएंगी। राज्य राजमार्गों के साथ सभी ग्रामीण सड़कों को जोड़ देंगे। 373 सिंचाई और निकासी नहरों पर लकड़ी के पुल के बजाए कंक्रीट के पुल बनाए जाएंगे। सभी हाइवे पर आसानी से पहुंच के अंदर प्रभावी ट्रामा केयर यूनिट स्थापित की जाएंगी, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में कमी आए।

5. संरक्षण, कृषि और परिवहन के लिए पानी के संसाधन

जल धरो जल भरो योजना का विस्तार किया जाएगा जिससे सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी पहुंचे। राज्य की 295 नदियों और सहायक नदियों का बहुआयामी परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जर्मनी में राइन नदी जैसी नदियों की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए इनका लाभ उठाया जाएगा, जो न केवल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है बल्कि पर्यटन को भी आगे बढ़ाती है

6. आर्सेनिक मुक्त पानी के लिए टास्क फोर्स का गठन

राज्य सरकार आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगी। राज्य के 7 जिलों के 83 ब्लॉकों में 1.98 करोड़ लोग सीधे तौर पर पानी मे पाये जाने वाले आर्सेनिक से प्रभावित हैं। यह टास्क फोर्स 65,000 गांवों में पाइप लाइन के जरिए साफ पानी पहुंचाने का काम करेगी

7. चेक डैम का निर्माण, कुएं और कृषि तालाब की खुदाई

राज्य सरकार सभी आवश्यक स्थानों पर चेक डैम के निर्माण के साथ ही कुएं और कृषि तालाबों की खुदाई कराएगी। ये आपदा प्रबंधन में मदद करने के साथ ही नजदीकी गांवों में घरेलू और कृषि कार्यों के लिए पानी की आपूर्ति में सुधार करेंगे

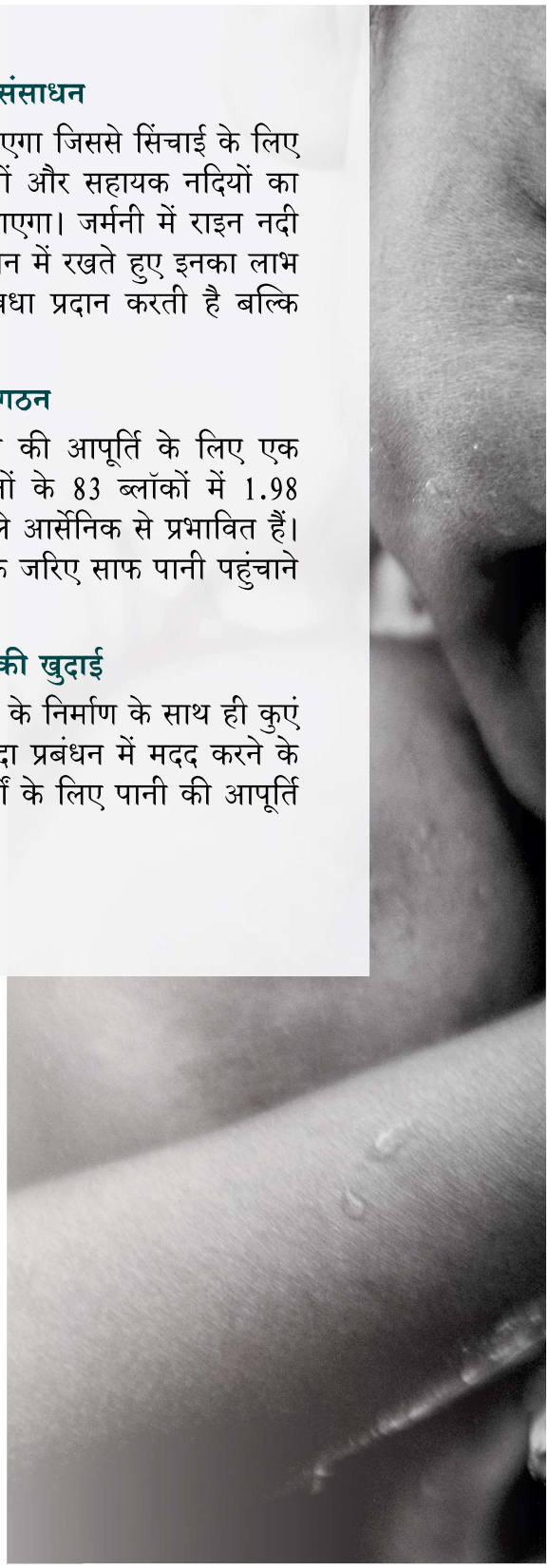

हम अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध और सर्वदा समर्पित हैं। विगत दशक सभी क्षेत्रों में बंगाल के सर्वांगीण विकास का साक्षी रहा है। हम बंगाल को अधिकतम ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपका अटल सहयोग चाहते हैं।

बंगाल की विरासत, इसके संघर्ष का इतिहास और इसकी प्रतिष्ठा की हर हाल में रक्षा करनी चाहिए। समाज को बांटने की इच्छा रखने वाली विभाजनकारी ताकतों को रोका जाना चाहिए। बंगाल के विकास के लिए तृणमूल कांग्रेस ने जो संघर्ष किये इसे लोग ही और सुदृढ़ कर सकते हैं।

बंगाल में शांति, एकता और विकास के लिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दीजिये।

आपका विश्वास, आत्मविश्वास तथा आपकी निष्ठा इस यात्रा में हमारी ताकत है। सभी विभाजनकारी ताकतों के कुप्रचारों, धन बल और बाहुबल के खिलाफ बंगाल हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से खड़ा होता रहा है। इतिहास को ध्यान में रखते हुए 17वें विधानसभा चुनाव में पूरे राज्यभर में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने की यह हमारी अपील है।

बांग्ला नववर्ष के पूर्व शुभकामनाओं, बधाई तथा अभिवादन के साथ

जय हिंद, जय बांग्ला

द्वारा प्रस्तुत

ममता बैनर्जी

हमें फॉलो करें

AITCofficial

AITCofficial

aitcofficial

www.aitcofficial.org

बंगाल की विरासत और गर्व की रक्षा करें
इस चुनाव चिह्न पर अपना वोट दें

सुब्रत बख्शी, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्थ चटर्जी, महासचिव, तृणमूल कांग्रेस
द्वारा प्रकाशित और मेट्रोपोलिटन डिज़ाइन सेन्टर, कोलकाता - 700001 द्वारा मुद्रित

AITCofficial aitcofficial AITCofficial